[2009] 6 एस.सी.आर. 1123

राजस्थान राज्य ....अपीलकर्ता

बनाम

हेमराज और अन्य। ....प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या 847 / 2009

अप्रैल 27, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 376(2)(g) स्पष्टीकरण 375 और 34 - महिला, क्या बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जा सकता है - माना गया: बलात्कार की परिभाषा के मद्देनजर, किसी महिला को बलात्कार के लिए दोषी ठहराना अवधारणात्मक रूप से अकल्पनीय है - धारा 376(2) के स्पष्टीकरण में घटित होने वाला सामान्य इरादा महिला पर लागू नहीं होता।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या एक महिला आईपीसी की धारा 376(2)(g) के तहत दोषी ठहराई जाने योग्य है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निर्णय किया

1.1. आईपीसी की धारा 375 को पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि बलात्कार केवल एक पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। यह धारा स्वयं यह बताती है कि कब किसी पुरुष के बारे में कहा जा सकता है कि उसने बलात्कार किया है। आईपीसी की धारा 376(2) बलात्कार के गंभीर मामलों की कुछ श्रेणियां बनाती है, क्योंकि उनमें अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। उनमें से एक "सामूहिक बलात्कार" से संबंधित है। उप-धारा (2)(जी) की भाषा में प्रावधान है कि "जो कोई भी 'सामूहिक बलात्कार' करेगा उसे दंडित किया जाएगा आदि। स्पष्टीकरण में केवल यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी महिला के साथ उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के समूह में एक या अधिक द्वारा बलात्कार किया जाता है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का इरादा सामान्य माना जाएगा कि उपधारा (2) के अंतर्गत

सामूहिक बलात्कार किया। इससे किसी महिला को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह संकल्पनात्मक रूप से अकल्पनीय है। [पैरा 7] [1128-बी-डी]

1.2. डीमिंग प्रावधान के संचालन से, जिस व्यक्ति ने वास्तव में बलात्कार नहीं किया है, उसे बलात्कार किया हुआ माना जाता है, भले ही समूह में से केवल एक ने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किया हो। "सामान्य इरादे" को आईपीसी की धारा 34 में वर्णित किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह उसके द्वारा अकेले किया गया था। "सामान्य इरादा" एक साथ कार्रवाई को दर्शाता है और आवश्यक रूप से एक पूर्व-व्यवस्थित योजना, दिमाग की पूर्व बैठक और कार्रवाई में भागीदारी के एक तत्व को दर्शाता है। कार्य अलग-अलग हो सकते हैं और चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जो एक ही इरादे या समान इरादे से भिन्न होता है। आईपीसी की धारा 34 को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यह कार्य आपराधिक कृत्य करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। धारा 376(2) के स्पष्टीकरण में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति "उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में" बलात्कार करने के इरादे से संबंधित है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी महिला का इरादा बलात्कार करने का था। [पैरा 7] [1128-ई-एच; 1129-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 8472

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 9.1.2007 से एस.बी. क्रिमिनल लीव टू अपील संख्या 99/2006।

अपीलकर्ता की ओर से वी. मधुकर, जयेंद्र सवादा और मिलिंद कुमार।

इम्तियाज अहमद, नगमा इम्तियाज और इक्विटी लेक्स एसोसिएटीज प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2 अलवर के फैसले की यथार्थता पर सवाल उठाने की इजाजत देने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में ' आईपीसी') की धारा 342 और 376(2) के तहत दंडनीय अपराध के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे। PW1 पीड़ित थी। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आरोपी चंदन ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। अन्य आरोपियों अर्थात् हेमराज और श्रीमती कमला के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं था। आरोपी चंदन किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'किशोर अधिनियम') के प्रावधानों के तहत मुकदमे का सामना कर रहा था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी हेमराज को आईपीसी की धारा 342 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया और कहा कि आरोपी कमला को आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । राज्य ने आईपीसी की धारा 376(2) से संबंधित आरोपों से प्रतिवादी को बरी करने पर सवाल उठाते हुए एक अपील दायर की । हाई कोर्ट ने माना कि जहां तक आरोपी हेमराज का सवाल है तो उसकी मौके पर मौजूदगी संदिग्ध थी। किसी भी स्थिति में दोनों प्रतिवादियों को आईपीसी की धारा 376(2) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

4. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 376(2)(जी) का दायरा और उससे जुड़े स्पष्टीकरण को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा कि बलात्कार के कथित समय पर आरोपी हेमराज की उपस्थिति स्थापित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, एक महिला यानी प्रतिवादी नंबर 2 को आईपीसी की धारा 376 (2)(g) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

6. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए धारा 375 और 376 पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक प्रासंगिक है वे इस प्रकार पढ़ते हैं:-

375. बलात्संग -

ऐसा पुरुष "बलात्कार" करने वाला माना जाता है, जो इसके बाद छोड़े गए मामले को छोड़कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में किसी महिला के साथ संभोग करता है

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दुसरा - उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा - उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां - उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां - उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

स्पष्टीकरण.-- बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।

अपवाद.--किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध बनाना बलात्संग नहीं है।]

376. बलात्संग के लिए सज़ा (1) जो कोई, उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, बलात्संग करेगा, उसे किसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो हो सकती है। आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की सजा और जुर्माने का भी दंडनीय होगा जब तक कि बलात्संग करने वाली महिला उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह वर्ष से कम उम्र की न हो, ऐसे मामलों में, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है:

बशर्ते कि अदालत फैसले में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से सात साल से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकती है।

(2) जो भी,--

xx xx xx xx xx

(g) सामूहिक बलात्कार करता है,

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है:

बशर्ते कि अदालत, फैसले में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से, दस साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है,

स्पष्टीकरण I.-- जहां एक महिला के साथ एक या अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, प्रत्येक व्यक्ति को इस उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार करने वाला माना जाएगा।

X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

7. धारा 375 को पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि बलात्कार केवल एक पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। यह धारा स्वयं यह बताती है कि कब किसी पुरुष के बारे में कहा जा सकता है कि उसने बलात्कार किया है। धारा 376(2)बलात्कार के गंभीर मामलों की कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। उनमें से एक "सामूहिक बलात्कार" से संबंधित है। उप-धारा (2) (जी) की भाषा में प्रावधान है कि "जो कोई भी सामूहिक बलात्कार करेगा" उसे दंडित किया जाएगा आदि। स्पष्टीकरण केवल यह स्पष्ट करता है कि जब किसी महिला के साथ उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के समूह में एक या अधिक द्वारा बलात्कार किया जाता है। सामान्य आशय से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को इस उपधारा (2) के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा। इससे किसी महिला को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह संकल्पनात्मक रूप से अकल्पनीय है। स्पष्टीकरण केवल यह इंगित करता है कि जब एक या अधिक व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करने के अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा। डीमिंग प्रावधान के संचालन से, जिस व्यक्ति ने वास्तव में बलात्कार नहीं किया है, उसे बलात्कार करने वाला माना जाता है, भले ही समूह में से केवल एक ने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए बलात्कार किया हो। "सामान्य इरादे" का वर्णन इसमें किया गया है आईपीसी की धारा 34 में यह प्रावधान है कि जब कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। "सामान्य इरादा" एक साथ कार्रवाई को दर्शाता है और आवश्यक रूप से एक पूर्व-व्यवस्थित योजना, दिमाग की पूर्व बैठक और कार्रवाई में भागीदारी के एक तत्व को दर्शाता है। कार्य अलग-अलग हो सकते हैं और चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित किया

जाना चाहिए, जो एक ही इरादे या समान इरादे से भिन्न होता है। आईपीसी की धारा 34 को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यह कार्य आपराधिक कृत्य करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। धारा 376(2) बलात्कार करने के इरादे से संबंधित है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी महिला का इरादा बलात्कार करने का था। इसलिए, अपीलकर्ता के वकील का कहना सही है कि अपीलकर्ता पर धारा 376(2)(जी) के तहत दंडनीय अपराध के कथित कमीशन के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

8. अपील निराधार है, खारिज करने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपील खारिज।

Digitally signed by RAHUL ANAND
Date: 2023.10.16 15:06:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court